CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

उत्तराखंड डेयरी विकास के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा

देहरादून सचिवालय में हाल ही में एक समीक्षा बैठक में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना का अनावरण किया। किसानों की आजीविका में सुधार और चारे की कमी को दूर करने पर ध्यान देने के साथ, मुख्यमंत्री ने 600 बहुउद्देश्यीय दुग्ध सहकारी समितियों, 20 चारा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), 50 दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों और 16 बद्री गाय विकास की स्थापना के निर्देश दिए।

ये व्यापक डेयरी विकास पहल उत्तराखंड में डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए तैयार हैं। बहुउद्देश्यीय दुग्ध सहकारी समितियों, चारा एफपीओ, दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों और बद्री गाय विकास केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार करना, दूध उत्पादन में वृद्धि करना और राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इन पहलों से एक स्थायी और समृद्ध डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे उत्तराखंड में सभी दुग्ध संघों और दुग्ध संघों को लाभ होगा।

मेघालय में गायों में गांठदार त्वचा रोग में कमी पाई गई है

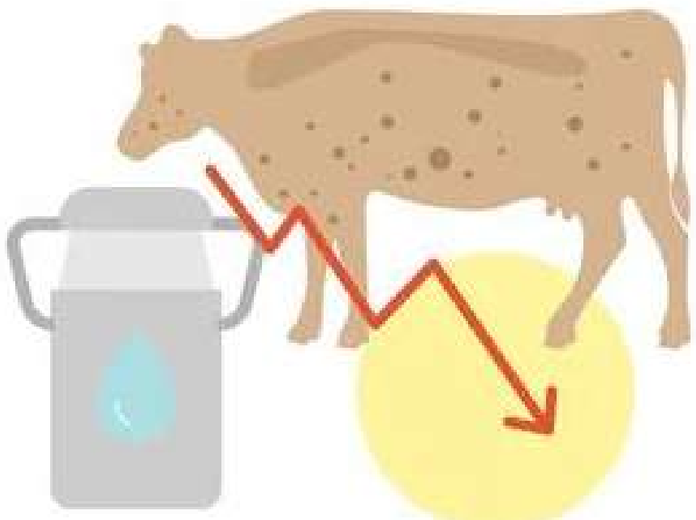

पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने पुष्टि की है कि मवेशी गायों में गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) का प्रसार कम हो रहा है। मवेशी गायों में गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) का प्रसार घटती दर पर रहा है, पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा घोषित इस बीमारी की बारीकी से निगरानी की गई है।

डॉ. ब्ला वार के अनुसार, हाल की रिपोर्टें पिछले दिनों की तुलना में एलएसडी संक्रमण की दर में कमी का संकेत देती हैं। स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बीमारी के आगे प्रसार को रोकने के लिए व्यापक उपाय लागू किए हैं।

डॉक्टर के मुताबिक करीब 168 रैपिड रिस्पांस टीमें एलएसडी के प्रसार पर कड़ी नजर रख रही हैं, क्योंकि आज तक इसका कोई इलाज नहीं है।

जैव सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देकर और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करके, AH&V का उद्देश्य एलएसडी को नियंत्रित करने और लंबे समय में गायों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है।

दूध परिवहन के लिए ट्रक-ऑन-ट्रेन (टीओटी) सेवा शुरू की गई

ट्रक-ऑन-ट्रेन, एक रोल-ऑन और रोल-ऑफ (RORO) सेवा, न्यू पालनपुर से न्यू रेवाड़ी स्टेशनों के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) पर शुरू की गई थी, ताकि इस क्षेत्र में दूध और मवेशी का परिवहन किया जा सके।

पहली सेवा 10 जून को स्टेशनों के बीच शुरू हुई। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष और अध्यक्ष की उपस्थिति में बनास डेयरी में RORO सेवा को हरी झंडी दिखाई गई।

DFCCIL और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके हाथ मिलाया है, जो MoU के तहत पहले प्रयास के रूप में किया गया है। गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रकों/दूध के टैंकरों को ले जाने और वापस लौटते समय किसानों/दुग्ध संघों के लिए पशु चारा ले जाने के लिए दोनों ओर से प्रतिदिन 25 लोडेड ट्रकों के साथ टीओटी सेवा शुरू की गई है।

25 ट्रकों के लिए अर्जित भाड़ा प्रति ट्रिप 7.25 लाख रुपये है। रसद लागत में समग्र कमी से दीर्घावधि में इस आवश्यक वस्तु की कीमत को विनियमित करने में मदद मिलने की उम्मीद है

असम अंतर-राज्यीय मवेशी परिवहन के लिए ऑनलाइन अनुमति प्रणाली की शुरुआत करता है

असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने मवेशियों के अंतर-राज्य परिवहन के लिए एक ऑनलाइन अनुमति प्रणाली शुरू की है। डेयरी उद्देश्यों में शामिल व्यापारियों को अब मवेशियों को असम से लाने और ले जाने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस प्रणाली के कार्यान्वयन से मवेशियों के परिवहन के आसपास सतर्कता बढ़ाने और नियमों को कड़ा करने की उम्मीद है।

मवेशियों के परिवहन की यह ऑनलाइन अनुमति केवल डेयरी के लिए मान्य है, बीफ के लिए नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले जिलों को छोड़कर, मवेशियों के अंतर-जिला आंदोलन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मवेशियों को अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में ले जाना चाहता है तो उसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी।

हाल ही में अधिनियमित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 में मवेशियों के अवैध परिवहन से निपटने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने प्रमुख सचिव मनीष ठाकुर और निदेशक इंदिरा कलिता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ऑनलाइन पोर्टल ahvd-cattletrans.assam.gov.in का उद्घाटन किया। मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि अब तक डेयरी उद्देश्यों के लिए मवेशियों के परिवहन की अनुमति ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त की जाती थी। हालांकि, वेब पोर्टल के लॉन्च होने के साथ विभाग अब मवेशी परिवहन के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं करेगा. ऑनलाइन अनुमति प्रणाली का उद्देश्य मवेशियों के अवैध परिवहन को रोकना और मवेशियों के कानूनी परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सहज निगरानी तंत्र स्थापित करना है।

मवेशियों के परिवहन की यह ऑनलाइन अनुमति केवल डेयरी के लिए मान्य है, बीफ के लिए नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले जिलों को छोड़कर, मवेशियों के अंतर-जिला आंदोलन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मवेशियों को अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में ले जाना चाहता है तो उसे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी।

भैंस पालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए TANUVAS भैंस मेला आयोजित करता है

तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (TANUVAS) ने भैंस पालन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए दो दिवसीय भैंस मेला आयोजित किया है। TANUVAS कॉलेज ऑफ फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी (CFDT), कोडुवेली द्वारा सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म के सहयोग से 14 जून और 15 जून को अपनी तरह का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्षेत्र के विशेषज्ञ भैंस किसानों के साथ बातचीत करेंगे।

आयोजन के पीछे का मकसद महिलाओं को भैंस पालन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कमाई का जरिया मुहैया कराना है। TANUVAS के अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु में भैंस की समृद्ध देशी किस्में हैं, लेकिन किसान उनसे उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

भैंस मेला के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है अधिक से अधिक महिलाओं को भैंस की खेती में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आय का एक स्रोत प्रदान करना। तमिलनाडु में देशी भैंस की किस्मों की एक विविध श्रेणी है, लेकिन कई किसान अपनी क्षमता को पूरी तरह से भुनाने में असमर्थ हैं।

सीएफडीटी के डीन डॉ. एन कुमारवेलु ने उत्पादकता बढ़ाने और पशुओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए भैंस पालन में वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने के महत्व को व्यक्त किया। भैंस मेले के दौरान ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रसार करके, TANUVAS का उद्देश्य किसानों को उनकी भैंस पालन प्रथाओं में सुधार करने और उनकी आय क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाना है।

यह आयोजन किसानों के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखने और साथी भैंस किसानों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे समुदाय और ज्ञान-साझाकरण की भावना को बढ़ावा मिलता है। TANUVAS कृषक समुदाय का समर्थन करने और स्थायी और लाभदायक भैंस पालन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

जून में उत्तराखंड में गांठदार त्वचा रोग के 4,000 से अधिक मामले सामने आए

उत्तराखंड में गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, राज्य में अकेले जून में 4,000 से अधिक संक्रमणों की सूचना दी गई है। ये नए मामले 5 मई से दर्ज किए गए कुल 16,235 मामलों में से लगभग एक चौथाई हैं। स्थिति की गंभीरता को इस तथ्य से उजागर किया गया है कि 303 मवेशियों ने बीमारी से अपनी जान गंवा दी है, जिसमें 5 जून को हुई 10 मौतों की रिपोर्ट भी शामिल है।

बागेश्वर जिले में 58 संक्रमित मवेशियों की मौत देखी गई, जबकि पिथौरागढ़ में बीमारी के कारण 25 लोगों की मौत हुई। वर्तमान में, उत्तराखंड में 2,076 सक्रिय मामले हैं, और मृत्यु दर 186% है। हालाँकि, कुछ सकारात्मक खबरें हैं क्योंकि 13,856 पशुधन एलएसडी से उबर चुके हैं, जो 85.34% की रिकवरी दर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उत्तराखंड के जिलों में, पिथौरागढ़ और बागेश्वर एलएसडी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इस साल अब तक क्रमशः लगभग 4,324 और 4,158 मामले दर्ज किए गए हैं। चंपावत 2,512 संक्रमणों के साथ निकटता से है, जिसमें सबसे अधिक 127 लोगों की मौत हुई है।

अधिकारियों ने पहाड़ी जिलों में कर्मचारियों की कमी के लिए मामलों की उच्च संख्या को जिम्मेदार ठहराया है। विभाग के एक वरिष्ठ चिकित्सक के अनुसार, पशुधन विस्तार अधिकारियों में लगभग 50% की कमी है और लगभग 25% पशु चिकित्सक के पद खाली हैं। कर्मचारियों की यह कमी प्रभावी रोग प्रबंधन और नियंत्रण उपायों में बाधा बन रही है।

एलएसडी के मामलों में वृद्धि ने उत्तराखंड में खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे इसके प्रसार को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों को कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने, अतिरिक्त संसाधन लगाने और पशुपालकों के बीच जागरूकता अभियान तेज करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसानों के स्वास्थ्य और आजीविका की रक्षा के लिए समय पर पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है।

असम ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1.16 लाख सेक्स्ड सॉर्टेड वीर्य की खरीद की

असम सरकार ने मादा बछड़ों की संख्या बढ़ाने और डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.16 लाख सेक्स सॉर्ट किए गए वीर्य की खरीद करके डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।यह कदम गुजरात जैसे राज्यों में सफल मॉडल से प्रेरणा लेते हुए दुग्ध उत्पादन को कई गुना बढ़ाने की राज्य की महत्वाकांक्षी योजना के अनुरूप है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम को भारत के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान दिलाने के उद्देश्य से राज्य की पशु-आधारित अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा है।

सीएम सरमा ने अपनी दृष्टि व्यक्त करते हुए कहा, "पशु-आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार करने से असम भारत के शीर्ष 5 राज्यों में पहुंच जाएगा। हमने गुजरात जैसे राज्यों के मॉडल का अनुसरण करते हुए अपने दूध उत्पादन को कई गुना बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।" इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, राज्य सरकार दुग्ध किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे उन्हें डेयरी उद्योग के विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

मादा बछड़ों की संख्या में वृद्धि के महत्व पर जोर देते हुए, सीएम सरमा ने राज्य के फंड का उपयोग करके 1.16 लाख सेक्स्ड सॉर्ट किए गए वीर्य की खरीद पर प्रकाश डाला। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य अधिक संख्या में मादा बछड़ों को सुनिश्चित करके डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो दूध उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री स्व नियोजन योजना के तहत, असम सरकार राज्य में प्रत्येक दो लाख युवाओं को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देगी।

सीएम सरमा ने कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला, जो अब नवजात बछड़ों के लिंग के निर्धारण की अनुमति देती है। वैज्ञानिक विधियों और कृत्रिम गर्भाधान के एकीकरण के माध्यम से, असम का लक्ष्य प्रजनन प्रथाओं को अनुकूलित करने और डेयरी उद्योग की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इन तकनीकों का लाभ उठाना है।

सीईडीएसआई ने आईटीसी सुनेहरा काल के सहयोग से पशु सखियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

बड़े जुगाली करने वाले जानवरों पर पशु सखियों को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आईटीसी सुनेहरा कल मिशन के लिए सीईडीएसआई द्वारा पहले दिन एक व्यापक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहले दिन एक क्षेत्र मूल्यांकन और उसके बाद चार दिनों का गहन प्रशिक्षण शामिल था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल समुदाय में पशु सखियों द्वारा उनकी आजीविका में योगदान देने के लिए सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है, बल्कि क्षेत्र में बड़े जुगाली करने वाले किसानों की आजीविका को भी बढ़ाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नस्ल चयन, आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन और विपणन सहित बड़े जुगाली करने वाले प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित किया गया, जिसमें 30 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

CEDSI : रिविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया